ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

सीजन में चने का साग न खाया तो क्या खाया?

रविवारीय, 14 - 20 मार्च 2021 वर्ष- दो, अंक-32, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

पर्यावरण संबंधी 50,000 से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित

स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट (एसओई) कहती है- पर्यावरणीय अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, निपटारों की प्रक्रिया सुस्त है देश में 2019 और 2020 के बीच वन्यजीव अपराधों की संख्या में गिरावट होने पर भी भारत में रोजाना दो मामले दर्ज होते हैं।, स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट कहती है कि अदालतें नए दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में बहुत कम दर से मामलों को निपटा रही हैं, जिससे लंबित मामलों का जखीरा और देरी बढ़ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में, पर्यावरण संबंधी 34,671 अपराध दर्ज किए गए थे। 7,000 से ज्यादा मामले पुलिस जांच में और लगभग 50,000 मामले अदालतों में लंबित थे। 2019 में भारत के कुल वन्यजीव अपराधों के 77 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। 2018 और 2019 के बीच, कुछ राज्यों में वन्यजीव अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई।

झारखंड में वनभूमि की लूट

मनोज कुमार शर्मा

डेढ़ साल पहले जब झारखंड सरकार ने यह बताया था कि राज्य में वनक्षेत्र में विस्तार हुआ है और कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत हिस्से पर वन हैं तो यह सजग लोगों के लिये एक सुकूनदेह खबर थी, पर हाल के कुछ वाकयों से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड में वनों के विस्तार उनकी सुरक्षा और हरियाली को लेकर कही गयी बातें जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। वास्तव में यहां हर रोज जंगलों का विनाश हो रहा है, उसमें आग लगायी जा रही है और एकड़ो एकड़ वनभूमि भूमाफियों, अतिक्रमण करने वालों के हाथों कब्जाई जा रही है। अफसोस यह सब सरकारी महकमें, सीओ, अफसरों की ही मिलीभगत से हो रहा है। यानि जिनके ऊपर जंगलों को बचाने, संवारने की जिम्मेदारी है वहीं इसे बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।

महज एक सप्ताह के अंदर की दो खबरों पर नजर डालें तो राज्य में वनभूमि कब्जाने की बात की पुष्टि होती है। शहर के फैलाव के कारण इससे सटे इलाकों में वनों एवं नदियों का अतिक्रमण तो आम बात है, पर राज्य के सुदूर इलाकों में भी वनों का विनाश जारी है।

राज्य में वास्तविक वन उजड़ रहे हैं। पहले ही सड़क निर्माण से लेकर विकास के नाम पर बड़े वृक्षों को काटा गया है और अब झारखंड में वनभूमि को भी बेचा और लूटा जा रहा है। हाल ही में हमें एक सजग पाठक ने बताया कि रांची लोहरदगा रेल रूट पर इटकी और टांगरबंसली के बीच रेल लाइन के किनारे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है उसकी वीडियो भी हमें भेजी। ग्रीन रिवोल्ट इस विषय को देखेगा भी। वहीं एक अध्ययन के रिपोर्ट के अनुसार देश भर के राज्यों में जंगलों में आग लगाने के मामले में झारखंड तीसरे पायदान पर है।

प्रतीकात्मक फोटो

सीओ ने ही साढ़े तीन सौ एकड़ वनभूमि की बंदोबस्ती कर दी

रामगढ़ जिले के मांडू अंचल में साढ़े तीन सौ एकड़ से ज्यादा वनभूमि वहां के सीओ ने लोगों के नाम पर बंदोबस्ती कर दी। इसमें खनन भूमि से लेकर, जंगल झाड़ और अधिसूचित वनक्षेत्र की भूमि शामिल है। मामले का खुलासा एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहजादा अनवर के एक शिकायत के बाद हुआ। शाहजादा अनवर ने वनभूमि समेत गैरमजरूआ जमीन के भूमाफियाओं एवं जमीन दलालों के नाम जमाबंदी की शिकायत की थी। जिसके बाद एक जांच कमिटी बनी और जांच में यह पकड़ में आया कि वनभूमि की लूट हुयी है। अब संबंधित अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि मांडू अंचल में कोई एक सीओ नहीं बल्कि अलग - अलग सीओ के समय में जमीन के अवैध बंदोबस्ती का खेल होते रहा है।

मूल बात है कि कार्रवाई का मकड़जाल तो चलेगा पर अब तक इन अवैध जमाबंदियों के बाद जंगल की जमीन पर वनों का खात्मा हुआ होगा, अवैध निर्माण भी हुये होंगे उसकी भरपाई कैसे होगी?

बोकारो में खरीद ली वन विभाग के नाक के नीचे 74 एकड़ वनभूमि

बोकारो जिले के तेतुलिया में 74 एकड़ वनभूमि को यूपी के रहने वाले एक व्यवसायी ने खरीद ली। मार्के की बात रही कि इस भूमि की वास्तविक कीमत जितनी आंकी गयी है उसके आधे से भी कम कीमत पर इस जमीन को व्यवसायी ने खरीद लिया है। बताया गया है कि यूपी के व्यवसायी ललन सिंह ने 23 करोड़ कीमत की जमीन को महज 10.30 करोड़ रूपये में खरीदा है। अब इस जमीन को राज्य सरकार वनभूमि बता रही है। सरकारी लापरवाही, विभाग के नींद में रहने का यह लाजवाब उदाहरण है।

बताया जा रहा है कि किसी इजहार हुसैन ने इस जमीन पर अपना दावा करते हुये इसे ललन सिंह को बेच दिया था। सरकार ने इजहार हुसैन के इस जमीन की जमाबंदी रद्द करते हुये इसे वनभूमि बताया था। लेकिन कोर्ट ने इजहार हुसैन के जमाबंदी को रद्द करने को नियम सम्मत नहीं माना और जमाबंदी रद्द करने के सरकारी आदेश को ही रद्द कर दिया। अब फिलहाल वनभूमि ललन सिंह की है।

अंदर ही अंदर सफाया

जंगल उजाड़ने और लकड़ी की तस्करी करने वालों का अपना एक तरीका होता है।वो सड़क या रेलवे लाइन से दिखने वाले किसी घने जंगल को बड़े ही सलीके से खत्म करते हैं। सीधे नजर आने वाले जंगल को वह छोड़ देते हैं, पर उसके अंदरूनी इलाके में जाकर बड़े पेड़ों का सफाया कर देते हैं। अक्सर इन घने जंगलों में जाकर देखें तो ये बाहर से जंगल की तरह दिखता है, पर इसके अंदरूनी इलाकों में बड़े पेड़ों के बजाय सिर्फ घनी झाड़ियां दिखेंगी। सैटेलाइट इमेज में यह भी हरियाली क्षेत्र में ही नजर आता है जिसे हम राज्य में वनों का विस्तार ही मान लेते हैं।

वृक्ष या सिर्फ झाड़ियां?

भले राज्य के 33 प्रतिशत के लगभग हिस्सों पर वनों के फैलाव का दावा किया गया है, पर हकीकत में इसमें एक बड़ा हिस्सा बड़े वृक्षों वाले घने जंगलों के बजाय झाड़ियों और लताओं का है। आज से कुछ दशक पहले रांची पहाड़ी पर भी बड़े वृक्षों वाले जंगलो की बहुतायत थी। अब उनमें भी कमी आयी है। पहाड़ी की हरियाली में अब पुटूश जैसी झाड़ियां भी हैं। जिसमें हाल ही में आग भी लग गयी थी ।

दरअसल किसी जंगल से बड़े वृक्षों की कटाई हो भी जाये तब भी वहां झाड़ियों और लताओं की उपस्थिति रहती है और हमें जंगल के होने का भ्रम होता है। लेकिन यह वास्तव में वृक्षयुक्त वन नहीं हैं? यहां से बड़े वृक्ष कट चुके होते हैं?

एक आपदा लील लेती है औसतन 20 लोगों की जान

एजेंसियां

पिछले पचास वर्षों में कुल 7,063 ऐसी आपदाएं आई हैं जिनमें कम से कम एक जान गई हो। इनमें 1,41,308 लोगों की मृत्यु हुई। यानी एक आपदा में औसतन 20 लोगों की जान गई। आंध्रप्रदेश, बिहार, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां अधिक जनसंख्या है वहां पिछले दो दशक में मौत के मामले भी अधिक हैं। विश्लेषण कहता है कि ऐसे स्थानों के लिए अलग आपदा प्रबंधन नीति बनाने की जरूरत है।

करीब 10 से अधिक जान लेने वाली आपदाओं पर नजर रखने वाली बेल्जियम स्थित संस्था ईएम-डीएटी का अनुमान है कि भारत में आपदाओं की वजह से पिछले पचास वर्ष में भारतीय मुद्रा में 72 खरब (99 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से भी अधिक का नुकसान हुआ है। ईएम-डीएटी-अंतरराष्ट्रीय आपदाओं के आंकड़ों का संग्रहण हैं। यहां उन सारे प्राकृतिक आपदाओं के आकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जिसमें दस से अधिक लोगों की जान गई हो हैं। आपदाओं में वृद्धि की वजह से एक ही स्थान पर कई तरह की आपदाएं आने लगी है। कुछ वर्ष पहले समुद्री इलाकों में सिर्फ चक्रवात की आशंका रहती थी, लेकिन अब इन्हीं इलाकों में लू जैसी आपदाएं भी अपना असर दिखाने लगीं हैं।

समुद्री इलाके में रहने वाले लोग चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं से परेशान रहते थे। लेकिन हाल के दशक में देखा गया है कि लू और आकाशीय बिजली से भी आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में लोगों की मौत हो रही है,'' राय कहते हैं। यह अध्ययन कहता है कि ओडिशा में बिजली गिरने से होने वाली मौतों में 61 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

बाढ़ और चक्रवाती तूफान जैसे मौसम संबंधी आपदा में सबसे अधिक जानें गई हैं। लू लगने से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। ओडिशा, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, केरल और महाराष्ट्र जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में आपदा में होने वाली मृत्यु का दर सबसे अधिक है। पिछले दो दशक में यह दर बढ़ी है।अध्ययन कहता है कि इन राज्यों में आपदा प्रबंधन की नीति को और पुख्ता करने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।जानकार सुझाते हैं कि आपदा से निपटने के लिए मौसम का सटीक पूर्वानुमान और असामान्य मौसम की मार सह सकने वाले निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना होगा

जीवन शैली आधारित बीमारियों व बचाव पर छात्रों को जागरूक करेगा बीएयू

संवाददाता

●राज्य के तीन विश्वविद्यालयों के 178 छात्र-छात्राएँ होंगे शामिल

●बीएयू के बीवोक कोर्स से जुड़े 88 छात्र-छात्राएँ भी लेंगे भाग

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय अंतर्गत कार्यरत सामुदायिक विज्ञान विभाग द्वारा झारखण्ड के छात्रों को जीवन शैली आधारित बीमारियों व बचाव विषय पर जागरूक करेगा. विभाग द्वारा राज्य स्तर पर जीवन शैली की बीमारियाँ एवं निदान में खाद्य विज्ञान और पोषण की भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला सह वोकेशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. 22 मार्च को आयोजित कार्यक्रम को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जायेगा.

कार्यक्रम में क्लिनिकल न्यूट्रीशनल एवं डायटेटिक्स सबंधी वोकेशल कोर्स से रांची विश्वविद्यालय, रांची के 50 छात्र-छात्राएँ ऑफलाइन मोड में तथा विनोवा भावे विश्वविद्यालय के 40 छात्र -छात्रायें ऑनलाइन मोड में शामिल होंगे. साथ ही बीएयू में संचालित बैचलर ऑफ़ वोकेशल इन ह्यूमन न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स के 48 तथा हर्बल रिसोर्स टेक्नोलॉजी के 40 छात्र-छात्रायें भाग लेंगे। विभागाध्यक्ष एवं पाठ्यक्रम समन्यवयक डॉ रेखा सिन्हा ने बताया कि जीवन शैली में आहार एक प्रमुख कारक हैं. जो कई बीमारियों के संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं. ये रोग हमारे तेज गति वाली जीवनशैली की गतिविधियों जैसे व्यायाम की कमी, भोजन, अत्यधिक कैलोरी का सेवन, धूम्रपान, अलौकिक उपभोग, तनाव, नींद की कमी आदि के परिणाम हैं. भारत में जीवनशैली से संबंधित रोगों की स्थिति काफी चिंताजनक है. ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे जीवनशैली में काफी बदलाव आया है. जिसकी वजह से भारत में तेजी से हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य गैर-संक्रामक रोगों के रोगियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है. यह रोग युवा वर्ग को भी काफी तेजी से प्रभावित कर रहे हैं. जिसे देखते हुए राज्य में डायटेशियन तथा न्यूट्रीशन कैरियर से जुड़े छात्र -छात्राओं को जागरूक करने की दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य के तीन विश्वविद्यालयों के कुल 178 छात्र - छात्रायें भाग लेंगे. तीनों विश्वविद्यालयों में कोर्स से जुड़े छात्र-छात्रायें पोस्टर,चार्ट, लीफलेट फ़्लैश बोर्ड के आईईसी सामग्री प्रतियोगिता में भी शामिल हो सकेंगे

इस कार्यक्रम में शहर के जाने - माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ वीके ढनढनिया, पटना के न्यूट्रीशन विशेषज्ञ डॉ संजय मिश्रा एवं सीआईपी के डायटेशियन आभा चन्द्रा विषयगत जानकारी देंगे।

पराली जलाने से निपटने के उपाय

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली के कृषि यांत्रिकीकरण के उप-मिशन पर फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय रूप से सहयोग कर रहा है। ताकि कृषि मशीनों और उपकरणों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार किराये के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध हों। यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी थी।

तोमर ने यह भी बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) बायोगैस और थर्मल उपचार के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा तकनीकों का उपयोग करके बायोगैस / बायोसीएनजी / ऊर्जा के उत्पादन के लिए धान की पराली / फसल के अवशेषों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी और एनजी) के तहत तेल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (एसएटीएटि) योजना के तहत स्वच्छ परिवहन के रूप में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) उत्पन्न करने के लिए चावल के भूसे सहित बायोमास / कचरे को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

सुरक्षा, लैंगिक समानता को स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है: सीएमडी सीसीएल

संवाददाता

रांची : सीसीएल मुख्यालय के 'कन्वेंशन सेंटर' में 08मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसका थीम 'महिला नेतृत्व : कोरोना काल में समान भविष्य की खोज था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती विमला प्रसाद,एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएमडी, सीसीएल, पी.एम. प्रसाद, कर्नल अर्चना भाटी, कुलपति, रांची यूनिवर्सिटी, डॉ कामिनी कुमार, निदेशक (वित्त) एचईसी श्रीमती सुश्री अरूण्धती पंडा, निदेशक तकनीकी वी.के. श्रीवास्तव एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, निदेशक विनय रंजन, निदेशक तकनीकी धर्मपत्नी श्रीमती बिन्दु सिंह,निदेशक एन.के. अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सीसीएल मुख्यालय, विभिन्न क्षेत्रों एवं केंद्रीय अस्पतालों के महिलाकर्मी सोशल डिस्टेंशिंग पालन करते हुये उपस्थित थीं। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलित कर किया।

समारोह की मुख्य अतिथि विमला प्रसाद ने उपस्थित सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में महिलाओं ने चाहे वह चिकित्सक हों, या वैज्ञानिक, या नर्स, या पुलिस कर्मी, या सफाई कर्मी या हमारी कोयला योद्धा होंसभी क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान से अपने नेतृत्व क्षमता का उदाहरण पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सहभागिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

सीएमडी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीसीएल को सभी सार्वजनिक उपक्रमों के समक्ष महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित वातावरण एवं लैंगिक समानता जैसे मापदंडों पर एक मॉडल संस्थान के रूप में स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है।

दिल्ली के जंगल में नीलगाय, तेंदूआ, लकड़बग्घा,बिज्जु

एजेंसियां

दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी और ट्रैफिक की भीड़भाड़ के बीच जंगल और जंगली जीव की उपस्थिति के बारे में शायद ही कोई सोच सकता है, लेकिन हाल में आए एक सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में सामने आया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली से सटे अरावली के जंगल में वन्यजीवों की अच्छी-खासी आबादी है। वर्ष 2019 में किया गया सर्वे कहता है कि दिल्ली के आसपास वन्य क्षेत्र में जैवविविधता समृद्ध है। वह भी संरक्षण क्षेत्र से बाहर। यहां वन्यजीवों की खासी संख्या देखी गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद से सटा मांगर बनी का जंगल जानवरों की आवाजाही के लिए एक तरह से कॉरिडोर का काम करता है। जानकार मानते हैं कि ऐसे वनों के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। देश की राजधानी के इतने नजदीक होने के बावजूद भी हरियाणा के अरावली की गिनती देश के कुछेक सबसे खराब स्थिति वाले वनों में होती है। बीते सालों में यहां अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है। जंगलों की स्थिति इतनी खराब है कि यहां तेंदुए और इंसानों के बीच आए दिन संघर्ष की खबर आती रहती है। डब्लूडब्लूएफ इंडिया के सौजन्य से आए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बेहतर प्रबंधन से इस इलाके में वन्यजीव और इंसान के बीच संघर्ष को कम किया जा सकता है।

हालांकि हालिया सर्वे के बाद वन्यजीवों पर काम करने वाले काफी उत्साहित हैं। ''यह काफी सुखद और चकित करने वाला हैं। अरावली जैसे जंगल में भी भांति-भाति के स्तनपायी जीव मिले हैं। खासकर बिज्जू, लकड़बग्धा, लोमड़ी, सूर्ख नेवला और भूरे रंग के लंगूर का मिलना काफी चौंकाने वाला है। हालांकि, लंगूर की संख्या काफी कम है। गजाला शहाबुद्दीन जो पेशे से इकोलॉजिस्ट हैं। वे गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च (सीईडीएआर) के साथ सीनियर फेलो के तौर पर जुड़ी हैं कहती हैं कि ''महानगर के नजदीक इस तरह के जंगल का होना बड़ी बात है। यह लोगों के मनोरंजन, शोध और स्कूली बच्चों के सीखने के लिए एक शानदार मौका उपलब्ध करा सकता है,'' उन्होंने आगे कहा कि अंधाधुंध वन की कटाई, खनन और रियल एस्टेट की वजह से अरावली के जंगल को खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्ष 2012 से 2020 के बीच सिर्फ गुरुग्राम में अरावली के वन क्षेत्र में करीब 10,000 एकड़ का नुकसान हुआ है।

समृद्ध जैवविविधता समेटे बहुत पुरानी पर्वत-श्रृंखला है अरावली

गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को छूता हुआ अरावली पर्वत श्रृंखला 700 किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली के जंगल पर पिछले कई दशकों से काम करने वाले सुनील हर्सना कहते हैं कि वर्ष 2013 में पहली बार कैमरा ट्रैप में तेंदुए की तस्वीर आई थी। वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) के द्वारा वर्ष 2017 में एक अध्ययन किया गया जिसमें सामने आया कि इन जंगलों में 10 प्रजाति के स्तनपायी जीव रहते हैं। इस अध्ययन में पहली बार गुरुग्राम जिले में सांभर के होने की बात पता चली थी। साथ ही नीलगाय, सियार और खरगोश जैसे जीव शामिल हैं। दूसरी तरफ, अपेक्षाकृत अधिक शर्मीले स्वभाव के जीव के भी होने का अनुमान था। इनकी गणना के लिए गोबर, नाखून इत्यादि का सहारा लिया गया। इस श्रेणी में तेंदुए, जंगली बिल्ली आदि शामिल हैं। इस रिपोर्ट की लेखक परिधि जैन कहती हैं कि इस इलाके में संरक्षण के प्रयास तत्काल शुरु करने की जरूरत है।

बिगड़ रहा है देश का स्वास्थ्य

इंडिया फिट रिपोर्ट 2021 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के स्तर में वृद्धि के बारे में विस्तार से बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत से जीओक्यूआईआई (GOQii) में 50 लाख से अधिक लोग हैं जो स्वस्थ रहने के लिए इस मंच से जुड़े हैं। इन्हीं उपयोगकर्ताओं से स्वास्थ्य के अलग-अलग समस्या को लेकर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। हेल्थ रिस्क असेसमेंट (एचआरए) स्कोर के अनुसार 50.42 फीसदी या हर 2 में से 1 भारतीय 'हाई रिस्क' या 'बॉर्डरलाइन' श्रेणी में है। इसमें पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में 12 फीसदी का सुधार है इससे पहले 62 फीसदी भारतीय 'अस्वस्थ' श्रेणी में थे। सूरत, जयपुर और पटना भारत के शीर्ष 3 शहरों में रहने वाले लोग स्वस्थ हैं जबकि लखनऊ, कोलकाता और चेन्नई वाले अस्वस्थ हैं। यहां यह ध्यान देना दिलचस्प है कि महानगरीय शहरों में से कोई भी शीर्ष 3 स्वस्थ शहरों में नहीं है, भले ही उनके पास फिटनेस सुविधाएं और स्वास्थ्य केंद्रों तक अधिक पहुंच है। जीओक्यूआईआई की नवीनतम इंडिया फिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, अधिकांश लोग अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार करके स्वस्थ बन सकते हैं। लॉकडाउन ने भारतीयों को अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का समय दिया। रिपोर्ट में कहा गया के उम्र के लिहाज से, पुरानी पीढ़ी की तुलना में युवा पीढ़ी अधिक अस्वस्थ पाई गई है। कोरोना का डर, वित्तीय स्थिरता और वर्तमान कार्य भारतीयों के तनाव के स्तर को प्रभावित करने वाले शीर्ष 3 प्रमुख कारक हैं। जबकि दोनों महिला एवं पुरुषों को कोविड-19 का डर, स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में चिंता को जाता है। महिलाएं तनाव के दूसरे प्रमुख कारण के रूप में घर के काम का हवाला देती हैं। 4.83 फीसदी किशोरों में स्कूल और अध्ययन को लेकर तनाव पाया गया।

रिपोर्ट में यह पता चला कि पूरे वर्ष भर तनाव का स्तर बहुत अधिक रहा। सर्वेक्षण के परिणाम ने बताया कि वर्ष के मध्य में तनाव सूचकांक 4.98 से बढ़कर वर्ष के अंत में 5.11 तक की वृद्धि हुई। वर्तमान में 45 फीसदी लोग अवसाद से ग्रस्त बताए गए हैं। लगभग 13 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने उच्च कोलेस्ट्रॉल होने के बारे में बताया, यह एक ऐसा आंकड़ा है जो पिछले दो वर्षों से स्थिर बना हुआ है। दूसरी ओर केवल 4 प्रतिशत ने उल्लेख किया कि उन्हें हृदय से संबंधित समस्याएं हैं जो 2019 में 8.6 प्रतिशत थी। 2020 में लगभग 15 फीसदी लोगों ने उच्च रक्त चाप होने के बारे में बताया, जबकि 2019 में यह 13.4 फीसदी था। रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा पिछले 4 वर्षों में लगातार बढ़ा है।

कोविड-19 महामारी से पहले जनवरी से फरवरी के मध्य तक औसत उपवास (फास्टिंग) शुगर का स्तर 138 मिलीग्राम / डीएल था, जो कि मार्च के मध्य में अप्रैल तक बढ़कर 165 मिलीग्राम / डीएल हो गया।

गोवा में बढ़ रहा शार्क खाने का चलन

समुद्र में पाए जाने वाले शार्क को खाने का चलन भारत के समुद्री तटों पर पुरातन काल से चला आ रहा है। पर हाल में गोवा के कई रेस्टोरेंट में इसकी मांग बढ़ी है।

भारत में 160 प्रजाति के शार्क पाए जाते हैं जिसमें से 10 प्रजाति के शार्क को मारने पर पाबंदी है।सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो घूम रहे हैं जिसमें शार्क का मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट का जिक्र मिलता है। इनमें गोवा के समुद्री तटों पर शार्क के मांस बिकते देखे जा सकते हैं।संरक्षणकर्ता मानते हैं कि जानकारी के अभाव में लोग प्रतिबंधित शार्क भी खा सकते हैं, जिससे इनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। दुर्लभ प्रजाति के शार्क भी मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंस जाते हैं।समुद्र की बेहतरीन शिकारी शार्क के दांत इतने मजबूत होते हैं कि मछली और इंसान तो क्या पानी के नाव भी चबा जाए। बावजूद इसके शार्क इंसानों के आहार का हिस्सा रहे हैं। हाल के वर्षों में देखा गया है कि देश के समुद्री तट वाले इलाके में शार्क खाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर गोवा में। सोशल मीडिया पर देश में शार्क खाने की चर्चा तेज है। हाल ही में अमेरिका के वीडिया ब्लॉगर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह बात सामने आई कि अमेरिका में लोग शार्क शायद ही खाते होंगे, पर भारत के गोवा जैसे समुद्री तट पर शार्क खाने का चलन खूब फल-फूल रहा है। देश-विदेश के फूड ब्लॉगर देश में शार्क परोसने वाले रेस्टोरेंट की तस्वीरें और वीडियो जारी करते रहते हैं।

इनसीजन फिश नामक चेन्नई स्थित एक संस्था ने हाल ही में एक सर्वे किया। इससे पता चला कि गोवा के रेस्टोरेंट में शार्क से बनी खाने की सामग्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनसीजन नाम की यह संस्था देश में समुद्र में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को लेकर जागरुकता फैलाती है और समुद्री आबो-हवा को टिकाऊ बनाये रखने की वकालत करती है। यद्यपि संस्था द्वारा सर्वे के नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

हिमाचल के ट्राउट मछली पालक छोड़ने लगे अपना पेशा?

सिद्धार्थ सिंह

किसानों को अपनी ही सरकार से प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ रहा है। मछली का बीज बेचने वाले सरकारी संस्थान खुद भी बाजार में मछली बेचते हैं।

ट्राउट मछली पालने वाले हिमाचल के मछली पालक अपना पेशा छोड़ने को मजबूर हैं। मछली के बीजों की आपूर्ति न होने और बार-बार आने वाली बाढ़ से उन्हें नुकसान हो रहा है।समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मछली पालन करने वालों का बीमा भी कराना शुरू किया है ताकि आपदा की स्थिति में किसानों की क्षतिपूर्ति हो सके।

''सब कुछ मेरे सामने हुआ। मैंने बाढ़ के पानी को टैंक की तरफ आते हुए देखा। बाढ़ के पानी के साथ सारी मछलियां बहकर जाने लगीं। मैंने बदहवास हो गया। हाथों से ही मछलियों को रोकने की कोशिश करने लगा,'' हरीश धनोतिया अपना दर्द बयान करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगरा के रहने वाले धनोतिया मछली पालन का व्यवसाय करते हैं। उस बाढ़ ने धनोतिया को तोड़कर रख दिया। कुछ ऐसा नुकसान हुआ कि उन्होंने मछली पालन से तौबा ही कर ली।

स्वाद और पोषण से भरपूर ट्राउट मछली एक समय पहाड़ी इलाके के किसानों की तकदीर बदलने वाली मछली कहलाती थी। लेकिन बाढ़ और दूसरी समस्याओं ने इन क्षेत्र में मछली पालन को इतना विकट कर दिया कि अब लोग इस पेशे को छोड़ने को मजबूर हैं। ट्राउट मछली ठंडे पानी की मछली मानी जाती है। इसमें ओमेगा थ्री, फैटी एसिड नामक तत्व होता है। इस मछली को स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है।स्वास्थ्य के मद्देनजर इस मछली की खूबियों और इसको पालने में आने वाली कठिनाइयों की वजह से बाजार में इसकी कीमत 1,000 से 1,500 रुपए किलो तक होती है। धनोतिया को देखें। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की। उस नौकरी को छोड़ इन्होंने मछलीपालन का पेशा चुना था। यह 2015 की बात है। बार-बार आने वाली बाढ़ ने कुछ ऐसी स्थिति कर डाली कि धनोतिया ने महज पांच साल में इसे मछली पालन को छोड़ने का निर्णय ले लिया। बीते साल यानी 2020 में इन्होंने यह फैसला ले लिया था। जीवनयापन के लिए अब वे एक दुकान चलाते हैं।

ट्राउट पालना जुआ है

किसानों की मुश्किलें बढ़ाने में सिर्फ बाढ़ ही नहीं, बल्कि सरकार की बेरुखी का भी अच्छा-खासा योगदान है।देश के उत्तरी हिस्से के ट्राउट मछली पालक बीज, तारे और दूसरी जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर हैं। बावजूद इसके सरकार खुद भी इस बाजार में उतरकर मछली पालकों को प्रतिस्पर्धा दे रही है। हिमाचल सरकार ने भी मछली पालन के लिए ढ़ांचा खड़ा किया है। सरकार मछली पालन और मछली बेचने का काम भी करती है। सरकार के वृहत संसाधनों के सामने छोटे किसानों का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। किसानों का पक्ष यह है कि जिन सरकारी संस्थाओं पर मछली पालन से जुड़े जरूरी सामानों के लिए निर्भर हैं, उन्हीं संस्थाओं से इन्हें बाजार में मुकाबला भी करना पड़ रहा है। ट्राउट पालना किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है।

ट्राउट पालन न सिर्फ तकनीकी जटिलता वाला है बल्कि इनको बड़ा करने में समय भी काफी लगता है। एक बार तालाब पर बाढ़ या किसी दूसरी वजह से मुसीबत आई तो दोबारा उत्पादन शुरू करने में काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए कुल्लू में 2018 में आए बाढ़ से बाद जो किसान प्रभावित हुए थे वे अब तक मछली का उत्पादन शुरू नहीं कर पाए हैं।हिमाचल में सरकार के द्वारा कुल्लू स्थित पत्लिकुहल मछली फार्म से मछली के बीज बेचा जाता है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी फार्म है। यहीं से प्रदेश के हर किसान तक बीज और चारा जाता है।

''ट्राउट मछली पालने में असफल होने की भरपूर आशंका रहती है,'' कहते हैं नरेश कपूर, जो कभी मनाली के हरिपुर में एक बड़ा फार्म चलाते थे। उन्होंने वर्ष 2007 से 2013 तक ट्राउट पालन का काम किया।''पत्लिकुहल का फार्म समय पर चारा नहीं तैयार कर पाता है। वहां दक्षिण भारत के किसी राज्य से चारा तैयार करने का कच्चा माल आता है जिससे चारा तैयार करने में काफी समय लगता है,'' वह कहते हैं।

कई किसानों को शिकायत है कि सरकारी फार्म से खराब दर्जे का चारा मिलता है। कपूर ने बताया कि एक बार उन्होंने चारा खरीदा था जिसमें फंगस लगा हुआ था। ज्यादातर किसान मानते हैं कि चारे का बड़ा भाग खराब होता है।वर्ष 1989 में नॉर्वे की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ ट्राउट पालन की तकनीक हस्तांतरित करने का करार किया था। तब से हिमाचल में मछली पालन की तकनीक को अपडेट नहीं किया गया है। यहां की तकनीक पुरानी मानी जाने लगी है।

मछली पालन विभाग का कहना है कि विभाग सरकार पर किसानों की निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके लिए सब्सिडी के माध्यम से बीज और चारा तैयार करने वाले संयंत्र लगाने में निजी क्षेत्र की मदद की जा रही है। इस बात पर कपूर कहते हैं,''मेरा फार्म इलाके में सबसे बड़ा माना जाता था। मेरे पास खुद बीज तैयार करने का संयंत्र भी था, लेकिन बावजूद इनके मेरा फार्म नुकसान में गया।

कुल्लू में मछली पालन कर रहे किसान आशू कहते हैं, ''सरकार को हर किसी किसान को बीज और चारा बनाने की तकनीक देने पर ध्यान देने के बजाए इसके आपूर्ति पर ध्यान देना चाहिए।सरकार से हमें बीज और चारा मिलता है तो मुझे खुद इसे तैयार करने की क्या जरूरत है। एक तो खुद बीज तैयार करना महंगा है ऊपर से इसे चलाने के लिए भी लोगों को मजदूरी देनी होगी।

कर्ज और बाढ़ का कुचक्र

ट्राउट पालन की शुरुआत के लिए एक किसान को पहले एक विस्तृत ढांचा का निर्माण करना पड़ता है। इसपर काफी खर्च करना होता है। इसके लिए किसानों को अमूमन कर्ज लेना पड़ता है। बलबीर सिंह नामक एक किसान ने 48 लाख का कर्ज लेकर वर्ष 2008 में 18 रेसवे से फार्म शुरू किया था। रेसवे एक तरह का मानव-निर्मित पानी का ढांचा होता है जो मछलियां को पालने के लिए बनाया जाता है। इसमें उन्हें सरकारी सहायता भी मिली थी।शुरुआत में तो मछली पालन का काम काफी आकर्षक लगा। लेकिन जल्दी ही चारे और बीज की समस्याएं आने लगीं। सरकार के साथ सीधा मुकाबला तो था ही। मैं जैसे-तैसे फार्म चला रहा था। पर बाढ़ आई और सारी मछलियां खत्म हो गईं। इस वजह से इतना नुकसान हुआ कि कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया,'' सिंह कहते हैं। सिंह को 2013 में आखिरकार अपना मछली फार्म बंद करना पड़ा।

एक और मछली पालक आलम चांद के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कहते हैं, ''मैंने चालीस लाख का कर्ज लिया था। इसके लिए सरकार की मदद भी मिली। सब्सिडी की मदद से मछली पालने के लिए तीन टैंक स्थापित किए और बीज और चारा सरकार से लिया। वर्ष 2018 में बाढ़ ने सब तबाह कर दिया और सभी मछलियां मर गईं।'' इस काम को शुरू करने से पहले वे टैक्सी चलाकर गुजारा करते थे। काम बंद होने के बाद अब मजदूरी करते हैं।

ट्राउट के अंडे से बीज तैयार करना और चारा तैयार करना तकनीकी तौर जटिलताओं वाला काम है। मछली के बढ़ने की रफ्तार भी काफी धीमी होती है। मछली पालन विभाग से जुड़े एक उप संचालक ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि विभाग में कर्मचारियों की बेहद कमी है। ''विभाग के अलावा किसान भी हमारे निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करते। अगर किसान विभाग के साथ संपर्क में रहें तो नुकसान की गुंजाइश कम है,'' उन्होंने फोन पर बताया। कपूर कहते हैं कि मछली पालन विभाग में खुद कोई विशेषज्ञ नहीं है तो वे किसानों को क्या प्रशिक्षण देंगे? ट्राउट फिशरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति सिंह जामवाल ने कहा कि सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। ''सरकार को किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही, मछली पालन की तकनीक को अपडेट करने की भी जरूरत है। किसानो से जब ये पूछा गया कि नए लोगों को ट्राउट पालन में आने की सलाह देंगे? इसके जवाब में धनौतिया कहते, ''मेरा तो सिर्फ कर्जा हुआ बस, कुछ फायदा नहीं हुआ।''

सुंदरबन में अनदेखी की शिकार 'बाघ विधवाएं'

शहाना घोष

सुंदरबन में 45 लाख लोग और 86 बाघ रहते हैं। यहां बाघ की वजह से अपने पति को खोने वाली महिला को बाघ विधवा (टाइगर विडोज) कहते हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या यहां सैकड़ों में होगी।

सुंदरबन में संसाधनों की कमी की वजह से जंगली जीव और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। बाघ के हमलों में कई लोगों की जान भी चली जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी विधवाओं को कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है।परिवार चलाने की जिम्मेदारी के अलावा हादसे का आघात और सामाजिक भ्रांतियों की वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।

रॉयल बंगाल टाइगर के घर सुंदरबन के सतजेलिया गांव में सूरज ढलते ही लोगों के बीच अजीब सी मायूसी छा जाती है। मछली और केकड़ा पकड़कर पेट पालने वाली गीता मंडल अपना रोज का दुखड़ा याद करते हुए कहती हैं, ''पानी में मगरमच्छ का खतरा और जमीन पर बाघ का। ये क्या कम है कि अब हमारी जमीनें भी पानी में समा रही हैं। हम लोग का जीवन हर क्षण संकट में रहता है।''गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के बीच बने इस टापू को विश्व का सबसे बड़ा मेंग्रोव का जंगल माना जाता है। यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ भी है।

जंगल और बाघ की खासियत अपनी जगह पर इसने 55-वर्षीय गीता मंडल के जीवन को बेरंग कर दिया। बाघ के हमले में उनके पति की जान चली गई। इसके बाद गीता जीवन के संघर्षों का सामना अकेले कर रही हैं। पानी में मिलने वाली मछली और केकड़ा के सहारे वह अपना जीवनयापन कर रही हैं। सुंदरबन की देवी बनबीबी में आस्था रखने वाली गीता हर रात टापू पर पानी के किनारे जाल बिछाती है, जिसमें रातभर में मछलियां और केकड़े जैसे जीव फंस जाते हैं। हर सुबह वह इन्हें निकालकर घर ले जाती है। किनारे तक आने-जाने के दौरान कई बार गीता का सामना भी बाघ से हुआ है। गीता की पड़ोसी 45-वर्षीय सुभद्रा सान्याल भी अपने पुराने दिनों की याद में डूबी रहती हैं। पांच वर्ष पहले उनके पति को उनके आंखों के सामने ही बाघ गला दबोचकर ले गया। उस वक्त वह अपने पति के साथ मछली मार रही थीं।

सुमित्रा मिधा के पति मछली मारने गए थे और बाघ के शिकार बन गए। तब से मिधा की जिंदगी बगल गई। सुमित्रा मिधा के पति मछली मारने गए थे और बाघ के शिकार बन गए। तब से मिधा की जिंदगी बगल गई। हाल ही में सुमित्रा मिधा के पति मछली मारने गए थे और बाघ के शिकार बन गए। यह इलाका सुंदरबन टाइगर रिजर्व का है। इस घटना के बाद सुमित्रा का भरोसा बनबीबी से उठ सा गया है। बाघ के डर से उन्होंने मछली मारना छोड़ ही दिया और अब खेतों में मजदूरी करती हैं।

समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी से सुंदरबन मिट्टी के कटान से जूझ रहा है।यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अरबिन्द चौधरी कहते हैं कि ऐसे में बाघ की वजह से अपनों को खोने वाली महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ा है। चौधरी ने स्थानीय लोगों के साथ इस बारे में बातचीत की तो पता चला कि बाघ की वजह से विधवा हुई महिलाओं को लेकर इन इलाकों में ढेरों भ्रांतियां फैली हुई हैं। पर अगर मेडिकल शब्दावली का इस्तेमाल करें तो ये महिलायें पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्याएं जूझ रहीं हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपने साथ घटी या देखी गई घटनाओं पर वर्तमान में प्रतिक्रिया देता है। इसके कारण पुरानी बातों का बार-बार याद आना, बुरे सपने आना और ध्यान केंद्रित ना कर पाने जैसी समस्याए ं होती है। चौधरी को पीटीएसडी के शिकार लोगों में 72 लोग बाघ हमले से पीड़ित मिले।

''बाघ हमले के बाद कई बाघ विध्वाओं की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि वे समुद्र में या समुद्री नाले में जाकर केकड़ा, झींगा और मछली पकड़ने जैसे काम करने में भी डरती हैं,'' चौधरी कहते हैं।इस वजह से पीटीएसडी का असर इन महिलाओं की आय पर भी पड़ा है। यह जानना इसलिए भी खास है क्योंकि टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में अगर कोई बाघ के हमले में मारा जाता है तो उस मामले में सरकार की तरफ से घरवालों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। वर्ष 2010 से 2017 के बीच सुंदरबन के भीतर 52 लोगों की जान बाघ के हमले की वजह से चली गई।

वर्ष 2008 में हुए शोध में चौधरी और उनके साथी लेखकों ने पाया कि पिछले 15 वर्षों में 111 लोगों पर जानवर का हमला हुआ, जिसमें से 83 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल हैं। इसमें से 82 प्रतिशत लोगों की जान बाघ के हमले से गई। मगरमच्छ ने 10.8 प्रतिशत लोगों की जान ली और शार्क की वजह से 7.2 प्रतिशत लोग मारे गए। इन हमलों में 73.9 प्रतिशत लोगों की जान चली गई। ''करीब 94 प्रतिशत मामले में हमला टाइगर रिजर्व के आसपास हुआ जब पीड़ित अपना काम कर रहे थे।गांव वालों का मानना है कि कई मामले रिकॉर्ड में नहीं आते, क्योंकि ये हमले जंगल के अंदरुनी हिस्सों में होते हैं और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है।

बाघ विधवा पर ही पति की मृत्यु का ठीकरा

पुरुष की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी महिला पर आ जाती है। अपने बच्चों को पालने के लिए युवा महिलाएं उस इलाके को छोड़कर मजदूरी के लिए बाहर निकलने पर मजबूर हैं। गीता मंडल सतजेलिया गांव की हैं। इस गांव को स्थानीय लोग 'विधोवा पारा' यानी 'विधवाओं का गांव' के नाम से जानते हैं। गीता ने कहा कि पति के जाने के बाद अपने तीन बच्चों को पालने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया।

इस इलाके में बाघ के हमले के पीछे कई भ्रांतियां जुड़ी हैं। एक भ्रांति है कि जब देवी नाराज होती हैं तभी बाघ का हमला होता है। इस तरह पति की मृत्यु की जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर ही डाल दी जाती है।

क्या जंगल के कटने से फैलता है मलेरिया?

एक नए अध्ययन में कहा गया है कि जंगलों की कटाई से दक्षिणपूर्व एशिया में मलेरिया संक्रमण में शुरुआत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आगे चलकर इसमें कमी आ सकती है। क्षेत्र में मलेरिया की रोक-थाम संबंधी कार्यक्रमों के लिए बेहतर रणनीति विकसित करने में मदद करना है।

मच्छरों द्वारा मनुष्यों में मलेरिया परजीवी फैलाने के चलते संक्रमण पैदा होता है जो गंभीर और कभी-कभी घातक हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मेकांग नदी के किनारे के क्षेत्र में, कई निवासी आसपास के जंगलों में शिकार करते हैं और लकड़ी काटते हैं, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। क्षेत्र में हाल ही में हुए मलेरिया के प्रकोपों को वनों की कटाई से भी जोड़ा गया है।

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में स्नातक छात्र फ्रेंकोइस रेरोल कहते हैं कि देश अपने क्षेत्र में मलेरिया नियंत्रण और जंगलों के द्वारा इसके फैलने को कम करने का प्रयास करते हैं। मलेरिया की दरों पर वनों की कटाई के प्रभाव को समझना आवश्यक है।मलेरिया संचरण पर वनों की कटाई के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, रेरोल और उनके सहयोगियों ने ग्रेटर मेकांग के भीतर दो इलाकों में 2013 से 2016 तक वन कवर के आंकड़े और ग्राम-स्तरीय मलेरिया के आंकड़े दोनों की जांच की।

उन्होंने पाया कि पहले 2 वर्षों में वनों की कटाई की गतिविधियों के बाद, इलाके के गांवों में मलेरिया के संक्रमण में वृद्धि हुई, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें कमी आई।

अवसाद से ग्रस्त थे 21.7 फीसदी स्वास्थ्य कर्मी

कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से स्वास्थ्यकर्मियों पर काम का दबाव था, सीमित मनोवैज्ञानिक समर्थन के बीच उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आशंका ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2019 से अगस्त 2020 की अवधि में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मानसिक दबाव की स्थिति का अध्ययन करने वाले करीब 65 शोधों का विश्लेषण किया है जो 21 अलग-अलग देशों में किए गए थे।

इस अध्ययन से पता चला है कि करीब 21.7 फीसदी स्वास्थ्य कर्मी अवसाद से ग्रस्त थे। 22.1 फीसदी चिंतित थे जबकि 21.5 फीसदी अन्य तरह के मानसिक तनाव (पीटीएसडी) से ग्रस्त थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि इस समय में विश्व की करीब 4.4 फीसदी अवसाद से ग्रस्त थी, जबकि 3.6 फीसदी अन्य तरह के मानसिक विकार जिनमें पीटीएसडी भी शामिल है, का सामना कर रहे थे।

सूरज की रोशनी से पैसा बना रहे गुजरात के ग्रामीण किसान

अतहर परवेज

गुजरात के ढुंडी गांव में ग्रामीणों ने फसल की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू किया है। सिंचाई के बाद बची ऊर्जा को मध्य गुजरात बिजली कंपनी को बेचकर ग्रामीण पैसा भी कमा रहे हैं। बिजली कंपनी और किसानों के बीच हुए पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के तहत यह संभव हुआ है। किसानो ने कृषि कार्य के लिए 25 वर्ष तक सिर्फ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का अनुबंध किया है। इस अनुबंध के तहत सौर ऊर्जा से बची हुई बिजली कंपनी खरीद लेगी। इस तरह के अनुबंध से पर्यावरण को काफी फायदा हो सकता है। जानकार मानते हैं कि बिजली का समुचित इस्तेमाल करने से किसानो को सीधे फायदा होगा और इससे भूजल का दोहन भी कम होगा।

भारत में वर्ष 1951 में कृषि कार्य के लिए बिजली से चलने वाले करीब 5000 पंप थे। वर्तमान में ऐसे पंप की संख्या 2 करोड़ 50 लाख के करीब है। सूरज की रोशनी ढुंडी गांव के लिए नया सवेरा लेकर आया है। गुजरात के खेड़ा जिला स्थित इस गांव में महज तीन साल पहले तक बिजली का ग्रीड नहीं था। सिंचाई के लिए किसान डीजल से चलने वाले पंप पर आश्रित थे। धुएं और शोर से निजात के लिए गांव के लोग बिजली बाट की जोह रहे थे। बिजली तो नहीं आई लेकिन गांव में सिंचाई के लिए ऊर्जा का स्रोत बना सूरज। इस सौर ऊर्जा के जरिए ग्रामीण न सिर्फ आत्मनिर्भर बने, बल्कि कंपनी को बिजली बेचना भी शुरू कर दिया।

इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (आईडब्लूएमआई) और सर रतन टाटा ट्रस्ट के साथ आईडब्लूएमआई- टाटा वाटर पॉलिसी रिसर्च प्रोग्राम (आईटीपी) जैसी संस्थाओं के साझा प्रयास की वजह से ढुंडी गांव के लोगों ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया। तीन-चार साल पहले तक गांव में डीजल से चलने वाले करीब पचास पंप थे। पर अब स्थिति बदल गई है, कहते हैं राहुल राठौड़ जो आईडब्लूएमआई के सलाहकार हैं।''किसानों को अब डीजल पंप के शोर से निजात मिल चुकी है। पंप से निकलने वाले धुएं का भी सामना नहीं करना पड़ता। पंप चलाने के बाद जो बिजली बचती है उसे गांव के लोग बिजली कंपनी को बेच भी रहे हैं,'' राहुल ने बताया।

अनुबंध के मुताबिक मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल) इस्तेमाल के बाद बची हुई बिजली खरीद लेती है जो ग्रामीणों ने सौर ऊर्जा से बनाई है। किसानों को इस तरह दो तरीके फायदा हो जाता है। एक तो पंप चलाने में डीजल इत्यादि पर खर्च नहीं करना पड़ता। दूसरे, बिजली बेचकर भी कुछ आमदनी हो जाती है। धुंधा गांव में सोलर पंप से ही खेत की सिंचाई हो रही है। ये पंप डीजल पंप की अपेक्षा काफी कम आवाज करते हैं।

पर्यावरण के हित में है यह आमदनी

गांव के नौ किसानो के सहकारिता समूह सोलर पंप इरिगेटर्स कॉपरेटिव एंटरप्राइज (एसपीआईसीई) से इस सबकी शुरुआत होती है। एमजीनीसीएल ने ऐसे मीटर लगाए हैं जिससे किसानों द्वारा कंपनी को दिए ऊर्जा का हिसाब-किताब रखा जा सके। गांव के बाहर निकलने वाली बिजली की जानकारी एक मुख्य मीटर के जरिए की जाती है। इसकी मदद से पूरे गांव द्वारा पैदा की गई बिजली का पैसा गांव में एक मुश्त भेजा जाता है। गांव के लोग अपने-अपने मीटर के मुताबिक उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं। ढुंडी में चल रहे सहकारिता समूह को देश में अपने आप में अनोखा माना जा रहा है।

आईडब्लूएमआई के सीनियर फेलो तुशार शाह कहते हैं कि आईटीपी ने किसान के साथ सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के बारे में चर्चा की। किसानों को आशंका थी कि सूरज की रोशनी से चलने वाले पंप सिंचाई के मामले में कारगर होंगे या नहीं। किसानो को बताया गया कि सौर ऊर्जा से न सिर्फ सिंचाई हो सकती है, बल्कि उन्हें बिजली बचाने के एवज में पैसा भी दिया जाएगा। किसानो ने बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा के संयंत्र खरीदने के लिए पांच-पांच हजार रुपए की राशि जमा की। जनवरी 2016 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। सौर ऊर्जा के संयंत्र को बिजली विभाग के ग्रीड से जोड़ने में तीन महीने का समय लगा।

जब यह संयंत्र चल पड़ा है तो हर किसी का संदेह खत्म हो गया,'' शाह ने बताया। इस समूह से चार और किसान जुड़ गए हैं खेतों में सिंचाई करना अब हमारे लिए अधिक आसान है। पानी उपलब्ध होने पर टमाटर जैसी सब्जियां भी हम उगा पा रहे हैं,'' वह कहते हैं। गांव के दूसरे किसान उदय भाई कहते हैं कि पहले दो बीघा (एक बीघा यानी 1.7 एकड़ जमीन) सिंचाई के लिए 250 रुपए खर्च करने होते थे। ''अब मैं हर महीने लगभग सात हजार की बिजली बेच देता हूं। बिजली उत्पादन के लिए कोई खर्चा भी नहीं होता है,'' उन्होंने बताया।

कुछ किसान सोलर पैनल की वजह से खेती प्रभावित होने को लेकर चिंतित थे। हालांकि, कार्यक्रम सफल होने के बाद उनके विचार बदल गए हैं। ''मुझे पहले लगता था कि सोलर पैनल से खेत का बड़ा हिस्सा ढक जाएगा, लेकिन अब पता चला है कि इसमें बहुत अधिक जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है। सोलर पैनल के नीचे पालक और बैगन जैसे कई पौधे उगाए जा सकते हैं,''इस समय भारत सरकार हर साल 70 हजार करोड़ रुपए सिंचाई के लिए बिजली और पंप सब्सिडी पर खर्च कर रही है। अगर सौर ऊर्जा से किसानो को जोड़ दिया गया तो वर्ष 2022 तक वैकल्पिक स्रोत से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

फेस मास्क बन रहे हैं दूसरी बड़ी प्लास्टिक समस्या

डिस्पोजेबल फेस मास्क महासागरों में समा रहे हैं, जहां ये सूक्ष्म आकार में टूटकर 5 मिमी से छोटे कण उत्पन्न करता है। एक सप्ताह के अंदर ये कण अति सूक्ष्म कणों में टूट जाता है जिसे नैनोप्लास्टिक कहा जाता है

फेस मास्क कोरोनावायरस और अन्य बीमारियों के फैलने से रोकने में मदद करते हैं, कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगभग सभी स्वास्थ्य समूहों और देशों द्वारा बड़े पैमाने पर लोगो को मास्क का उपयोग करने को कहा गया। प्लास्टिक उत्पादों की तरह "फेंकने वाली जीवन शैली" के तहत, डिस्पोजेबल मास्क 2003 के सार्स से कोविड-19 तक महामारी का प्रतीक रहा है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि कितने मास्कों का निपटान किया जाता है। हाल के अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में हम हर महीने 129 अरब फेस मास्कों का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि हम हर मिनट 30 लाख मास्कों का उपयोग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक माइक्रोफाइबर से बने डिस्पोजेबल फेस मास्क हैं।

शोध में चेतावनी दी गई है कि मास्कों के अनुचित तरीके से निपटान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से पर्यावरणीय खतरे बढ़ सकते हैं, इन खतरों की पहचान कर इसे अगली प्लास्टिक की समस्या बनने से रोकना आवश्यक है। इस शोध की अगुवाई दक्षिण डेनमार्क विश्वविद्यालय के पर्यावरण विषविज्ञानी एल्विस जेनबो जू और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जियाओंग जेसन रेन ने की है।

मास्क रीसाइक्लिंग के लिए अलग से कोई दिशानिर्देशों का न होना

डिस्पोजेबल मास्क प्लास्टिक से बने उत्पाद हैं, जिन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक रूप से फैलने वाले सूक्ष्म प्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक जैसे छोटे प्लास्टिक कणों में टूट सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क का विशाल उत्पादन प्लास्टिक की बोतलों की तर्ज पर हो रहा है, जिनका प्रति माह उत्पादन 4300 करोड़ होने का अनुमान है।

बीएयू का एकदिवसीय तकनीकी एवं मशीनरी प्रत्यक्षण मेला संपन्न

संवाददाता

● कृषि के बिना देश एवं प्रदेश का विकास संभव नहीं : अशोक भगत

● यंत्र - मशीनरी तथा सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा में सरकार का प्रयास सराहनीय : डॉ ओएन सिंह

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग में शुक्रवार को एक-दिवसीय तकनीकी एवं मशीनरी प्रत्यक्षण मेला का आयोजन किया गया. दीप प्रज्ज्वलित कर मेला का उद्घघाटन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने कहा कि देश की बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी है. कृषि के बिना देश - प्रदेश का विकास संभव नहीं है. किसानों की बेहतरी के लिए समन्वित कृषि योजना पर फोकस करने की आवश्यकता है. किसानोपयोगी सुविधाजनक खेती औजार की दिशा में काफी सुधार आया है. खेती में महिलाओं की अधिक भागीदारी को देखते हुए छोटे - छोटे उपयोगी कृषि यंत्र को बढ़ावा सराहनीय कदम है. कृषि यंत्र के उपयोग के साथ कृषि कार्य में बैल का भी इस्तेमाल हो अन्यथा जैविक खेती को नुकसान होगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉ. ओएन सिंह ने कहा कि खेती किसानी जितनी आसान होगी, किसानों को उतना अधिक लाभ होगा. खेती को आसान बनाने में कृषि यंत्र एवं मशीनरी की बड़ी भूमिका है. देश भर में कृषि यंत्र - मशीनरी तथा सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में झारखण्ड सरकार की उल्लेखनीय व सराहनीय योगदान है. वि-श्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिकों ने भी कम मेहनत व कम लागतवाली औजार को विकसित कर कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है.

मौके पर भूमि संरक्षण निदेशक फणीन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बेहतर खेती के लिए जल संरक्षण पर जोर देते हुए 60 - 65 दिनों के बारिश जल का अधिकाधिक संचयन की बात कही. किसानों को नये एवं पुराने तालाबों का जीणोद्धार व जल निधि योजना तथा छोटे व सीमांत किसानों को सिंचाई हेतु पंप एवं पाइप की जानकारी देते हुए लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जासमीन के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि झारखण्ड में किसानों को कृषि यंत्र में सबसे अधिक अनुदान दिया जा रहा है. नई योजनाओं में मिनी ट्रेक्टर, मिनी पंप सेट एवं अल्टरनेटर का खेती में उपयोग हेतु महिलाओं के समुह को प्रशिक्षित कर 80 प्रतिशत अनुदान समुह को दिया जा रहा है. उपनिदेशक कृषि योजना संतोष कुमार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, बिरसा सर्विस सेंटर, कस्टम हायरिंग केंद्र व सोलर पंप सिंचाई आधारित सरकार की योजनाओं के बारे में बताया.

डीआर डॉ अब्दुल वदूद ने विवि द्वारा विकसित ग्यारह छोटे कृषि यंत्र को राज्य को समर्पित किये जाने को बड़ी उपलब्धि बताई. स्वागत भाषण, समारोह का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन प्रो डीके रूसिया ने किया. मेले में कृषि अभियंत्रण विभाग में कार्यरत शोध परियोजनओं के तहत डॉ उत्तम कुमार, डॉ प्रमोद राय, डॉ इरफ़ान अंसारी ने कृषि उपकरणों एवं मशीनों का प्रत्यक्षण एवं रख-रखाव, कृषि में प्लास्टिक का उपयोग, ड्रीप सिंचाई, नवीकरण उर्जा, कटाई उपरांत तकनीकी को प्रदर्शित किया. साथ ही छोटे उपकरण से जुड़ी फेमिना एग्रो, सोनालिका ट्रेक्टर तथा स्थानीय महिला सखी मंडली ने मसाला उत्पादों को भी प्रदर्शित किया।

मेले में राज्य के 14 जिलों के करीब 700 किसानों ने भाग लिया. मेले में जेएसएलपीएस, आरके मिशन, जासमीन, जेएमटीटीएल, जेटीडीएस, समेति एवं आत्मा संस्थाओं की विशेष भागीदारी रही. मौके पर ललन शर्मा, ओपी शर्मा, डॉ एमएच सिद्दीकी, डॉ जगरनाथ उराँव, डॉ एसके पाल, डॉ एस कर्मकार, डॉ पीके सिंह, डॉ बीके अग्रवाल सहित भारी संख्या में वैज्ञानिक भी मौजूद थे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्रामीण महिलाओं के लिए सत्र का आयोजन

संवाददाता

रांची : 08मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), सीएमपीडीआई ने बरकाकाना के बरदुडीह पंचायत के कडरू गांव की महिला निवासियों के लिए ''जागरूकता सत्र'' का आयोजन किया। इस सत्र में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। अच्छे समाज और ग्रामीण समुदायों होने के नाते तथा जरूरतमंद ग्रामीणों को पुराने कपड़ों के वितरण के साथ-साथ उन्हें प्रोटीनयुक्त खाद्य सामग्रियां भी वितरित की गयी। सीएमपीडीआई मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय संस्थान-3 के 20 विप्स सदस्य इस पहल को समर्थन करने के लिए उपस्थित थीं।

सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) सुनीता मेहता, मुख्य प्रबंधक (भूविज्ञान) सुश्री जेबा इमाम ने इस सत्र को सम्बोधित किया और उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराते हुए अपने बच्चों, परिवारों और समाज के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया। उन्हें खुद को और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वे अपने गांव की बेहतरी में योगदान दे सकें।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती पथिया देवी ने भी ग्रामीण महिलाओं की भूमिका एवं उनकी परिस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा महिलाओं को उनकी आजीविका और उनसे संबंधित मुद्दों और कठिनाइयों पर विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर बरदुडीह पंचायत के कडरू गांव की लगभग 60 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया।

डीएवी गांधीनगर की शिक्षिका को सम्मान

दहेज़ मुक्त झारखण्ड के बैनर तले ओरमांझी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डीएवी, गांधीनगर की वरीय शिक्षिका श्रीमती विनीता नंद को सम्मानित किया गया. समारोह में ओरमांझी के प्रखंड विकास पदाधिकारी एके स्वरूप ने प्रशस्ति - पत्र व मोमेंटो भेंट कर श्रीमती नंद को पुरूस्कृत किया। श्रीमती नंद को यह पुरस्कार विज्ञान विषय में 31 वर्षों की उत्कृष्ट शिक्षा कार्य तथा मानवता व समाज सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया. कार्यक्रम का आयोजन ओरमांझी में ओरमांझी आजीविका महिला संकुल संगठन के द्वारा किया गया था. मौके पर अंचल अधिकारी, दहेज़ मुक्त झारखण्ड की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सिंधु मिश्रा, थाना प्रभारी, स्थानीय पंचायतों की महिला मुखिया व महिला संकुल की सैकड़ो महिला भी मौजूद थी।

धनबाद- अल्लापूजा - धनबाद परिवर्तित मार्ग से जाएगी

दक्षिण मध्य रेलवे के सुलुर रोड तथा सोमानूर स्टेशन एवं कोयंबटूर तथा कोयंबटूर नॉर्थ स्टेशन के बीच ब्लॉक और कोयंबटूर तथा पोडानूर स्टेशन के बीच पुल की मरम्मत कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

दिनांक 13/03/2021 एवं 15/03/2021 को धनबाद से खुलने वाली ट्रेन संख्या 03351 धनबाद- अल्लापूजा स्पेशल ट्रेन कोयंबटूर स्टेशन के स्थान पर इरुगुर, पोडानूर स्टेशन होते हुए जाएगी तथा पोडानूर स्टेशन पर कोयंबटूर स्टेशन के समय सारणी का पालन होगा ।

दिनांक 15/03/2021 एवं 17/03/2021 को अल्लापूजा से खुलने वाली ट्रेन संख्या 03352 अल्लापूजा - धनबाद स्पेशल ट्रेन कोयंबटूर स्टेशन के स्थान पर पोडानूर, इरुगुर स्टेशन होते हुए जाएगी तथा पोडानूर स्टेशन पर कोयंबटूर स्टेशन के समय सारणी का पालन होगा ।

सीएमपीडीआई में भारत का अमृत महोत्सव का आयोजन

संवाददाता

रांची : 12मार्च को 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ''भारत का अमृत महोत्सव'' के उद्घाटन के अवसर पर ''गो ग्रीन ड्रिंक क्लीन'' विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएसआर) आलोक कुमार ने अमृत महोत्सव के बारे में सभी को संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि उत्सव की तैयारी 2022 में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से 75 सप्ताह पहले यानी 12 मार्च, 2021 से होनी है और यह 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के सभी महाप्रबंधक / विभागाध्यक्षगण तथा सभी क्षेत्रीय संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

75 सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव के उपलक्ष्य में सीएमपीडीआई (मुख्यालय) और इसके सभी क्षेत्रीय संस्थान द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित करने हेतु महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएसआर) द्वारा एक रोडमैप भी साझा किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का अमृत महोत्सव का थीम ''गो ग्रीन ड्रिंक क्लीन'' है एसलिए सीएसआर के द्वारा हरियाली बढ़ाने और समुदाय के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले स्कीमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानियों की वर्षगांठ जैसे समारोह पर जोर दिया जाना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक नेताओं के आसपास की घटनाओं को उठाया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों को भी याद किया जाएगा।

महिला कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन

रांची : 13मार्च को सर्वो, राँची अध्यक्षा श्रीमती रूबी अम्बष्ठ द्वारा रांची रेल मंडल में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि के सौजन्य एवं सर्वो रांची के सहयोग से मंडल के चिकित्सा विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। स्वास्थ्य शिविर में महिला कर्मचारियों के रक्तचाप , ब्लड शुगर तथा हड्डी की घनत्वता की जांच की गई। चिकित्सक के परामर्श पर कर्मचारियों के guided mammography की व्यवस्था भी की गई।

दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीमती ज़रीना फिरदौसी महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। उनके द्वारा केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि से प्रदत धनराशि से ही ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का संचालन अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीषा वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सर्वो, रांची उपाध्यक्षा श्रीमती अनुपमा पंडित, उपाध्यक्षा श्रीमती पायल पल्लवी एवं सदस्याएँ श्रीमती पूर्णिमा हेंब्रम, श्रीमती स्वाति आनंद, श्रीमती सोमा दास, श्रीमती आशा लता, श्रीमती बबीता तिवारी, श्रीमती दीपा पटेल व अन्य उपस्थित थी।

ग्रामीण महिलायें अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ : डॉ ओएन सिंह

संवाददाता

रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अंतरराष्टीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में विवि के महिला वैज्ञानिकों, शिक्षिका, गैर शिक्षिका, छात्राओं सहित अतिथि महिला कृषकों ने भी भाग लिया. मौके पर मुख्य अतिथि कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि देश-विदेश में कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार के क्षेत्र में महिलाएँ उल्लेखनीय कार्य कर रही है. खेत की मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल उत्पादन तक, फसल तैयार होने के बाद फसल का भंडारण, हैंडलिंग, मार्केटिंग समेत अन्य कार्यों में भी ग्रामीण महिलाएं अपनी भूमिका निभाती हैं. इन कार्यों के साथ ही महिलाएं मशरूम उत्पादन, मधुमख्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी और पशुपालन के आलावा फसल उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में भी अपना योगदान देती हैं. कुलपति ने कहा कि झारखण्ड व दुनिया के विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 60 प्रतिशत से भी अधिक है. वास्तव में पूरी दुनिया में महिलाएं ग्रामीण पारिवारिक पालन-पोषण एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास की रीढ़ हैं. मौके पर अतिथि महिला कृषकों को कृषि अभियंत्रण विभाग के सौजन्य से मक्का एवं सब्जी फसलों की शस्य कार्यो में उपयुक्त कम लागत वाली कृषि यंत्र मेज सेलर व डच हो वितरित किया।

डीन एग्रीकल्चर डॉ. एमएस यादव ने कहा कि समय के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में व्यापक बदलाव व सुधार आया है. आज कृषि शिक्षा में छात्राओं का काफी रूझान है और अनेकों महिलाएँ कृषि शिक्षा जुडी हुई है. डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने पशुपालन क्षेत्र में महिलाओं एवं इतिहास पर प्रकाश डाला. डायरेक्टर रिसर्च डॉ अब्दुल वदूद ने महिला सुरक्षा पर जागरूकता पर बल देते हुए बेटियों को बचपन से संस्कार व सुरक्षा को अहमियत देने की बात कही. डायरेक्टर सीड एंड फार्म ने आदिवासी महिलाओं का कृषि कार्यो में योगदान व समस्याओं को देखते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया.

कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय के एसोसिएट डीन प्रो डीके रुसिया ने कहा कि महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व में अधिकाधिक योगदान को देखते हुए पुरूषों द्वारा सम्मान दिये जाने की वकालत की

मौके पर महिला वैज्ञानिकों में डॉ नुतन वर्मा, डॉ स्वाती सहाय, डॉ सुप्रिया सिंह, डॉ नंदिनी कुमारी व डॉ स्वाती शबनम ने महिला को मानव का स्तम्भ व समाज की धुरी बताया. शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन डॉ नेहा पांडे ने की।

सीसीएल में गो ग्रीन, ड्रिंक क्लीन पर वेबिनार का आयोजन

संवाददाता

भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीसीएल मुख्यालय, रांची में 12 मार्च को 'वेबिनार' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व आईएफएस अधिकारी एस.एन. तिवारी, सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, एवं कर्मी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे। साथ ही विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीसीएल के क्षेत्रों से कर्मियों ने भी भाग लिया।

मुख्य वक्ता एस.एन. तिवारी ने भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत थीम 'गो ग्रीन, ड्रींक क्लीन' पर चर्चा करते हुये कहा कि जीवन संतुलन का विषय है और पर्यावरण एवं खनन में संतुलन होना चाहिए। उन्होंने अनेकों उदाहरण देते हुये कहा कि अगर हम पर्यावरण से कुछ ले रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण भी हमारा नैतिक कर्त्व्य है। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि हम पौधा रोपण के साथ-साथ पौधों की रक्षा भी करें। एसएन तिवारी ने भारत सरकार द्वारा घोषित अमृत महोत्सव की सराहना करते हुये कहा कि यह अवसर हमें अपने उपलब्धियों को याद करने के साथ-साथ भविष्य की नींव रखने का भी है। उन्होंने सीसीएल को अगले 75 सप्ताह तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शुभकमानएं दी।

वर्ष 2022 में देश को आजादी मिले 75 वर्ष पूरे होंगे इसी उपलक्ष्य में 'भारत का अमृत महोत्सव' का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) में भी अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्यालय परिसर में सीसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, सीवीओ एस.के. सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, श्रमिक प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण ने सोशल डिस्टेशिंग का पालन करते हुये बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया व स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया।

अवसर विशेष पर निदेशकगण एवं सीवीओ द्वारा सीसीएल मुख्यालय परिसर में स्थित उद्यान में पौधा रोपण किया गया। निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव ने कहा कि भारत का अमृत महोत्सव सभी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं गौरव गाथा को पुनः याद करने का अवसर प्रदान करता है। सीसीएल द्वारा इस महोत्सव के अंतर्गत 'गो ग्रीन, ड्रींक क्लीन' थीम पर विशेष महत्व देते हुये विभिन्न पहल एवं कार्यक्रम किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सीसीएल सदैव ही पर्यावरण सामंजस्य के साथ-साथ उत्पादन करने केलिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ईको पार्क, वृहद स्तर पर पौधा रोपण, पुष्प वाटिका एवं शुद्व जल की व्यवस्था जैसे कार्यो पर बल दिया जाता रहा है।निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में भारत का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि स्वतंत्रता से ही हम संप्रभुता प्राप्त करते हैं और इस स्-वतंत्रता को संजो कर रखना है। उन्होंने कहा कि सीसीएल द्वारा खदानों में संचित जल का उपयोग आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है।

सीवीओ एस.के. सिन्हा ने भारत का अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुये कहा कि देश की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित 'आजादी का अमृत महोत्सव' का आयोजन सीसीएल कर्मियों सहित आमजन को प्रेरित और उत्साहित करता है। महाप्रबंधक (सीएसआर) ए.के. सिंह ने अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि आज से 75 सप्ताह तक सीसीएल मुख्यालय सहित सभी कमांड क्षेत्रों में सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन वरीय प्रबंधक ए.डी. वाधवा ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महाप्रबंधक ए.के. सिंह एवं उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा।

फोटो न्यूज

कंकड़ पत्थर को सजा कर बना दी कलाकृति

कल्पना करें कि ये पेड़ न होते तो ये जगह कितना बदतर रेगिस्तान होता

जैव विविधता का लगातार नुकसान हो रहा है

एजेंसियां

अध्ययन से पता चला है कि प्रजातियों के भीतर विविधता के नुकसान के गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं, यह प्राकृतिक सामग्री और प्राकृतिक उत्पादों से स्वच्छ पानी और दवाएं प्रदान करते हैं। प्रजातियों के भीतर भिन्नता का नुकसान एक छिपी हुई जैव विविधता पर संकट की तरह है। एक नए अध्ययन में इस बारे में पता लगाया गया कि यह विविधता आवश्यक पारिस्थितिक कार्यों को किस तरह पूरा करती है और प्रकृति लोगों के लिए किस तरह फायदे पहुंचाती है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया सांता क्रूज (यूसी सांता क्रूज) में पारिस्थितिकी और विकासवादी जीव विज्ञान के प्रोफेसर एरिक पल्कोवाक्स ने कहा जैव विविधता का मतलब केवल प्रजातियों की संख्या नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक है, जब हम प्रजाति आधारित विलुप्ति की बात करते हैं, तो हम कहानी के केवल एक हिस्से पर प्रकाश डाल रहे होते हैं। एक प्रजाति के भीतर (इंट्रासेप्सिक) भिन्नता जैव विविधता का एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन इसका लोगों के लिए बहुत महत्व है, हमें जैव विविधता के इस रूप को पहचानने और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

यूसी सांता क्रूज़ के एक पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता सिमोन डे रोचेस के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि प्रजातियों के भीतर विविधता के नुकसान के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह प्राकृतिक सामग्री और प्राकृतिक उत्पादों से स्वच्छ पानी और दवाएं प्रदान करते हैं।

नए अध्ययन में उन्होंने किए गए अध्ययनों के वैज्ञानिक साहित्य का सर्वेक्षण किया, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक प्रजाति के भीतर (इंट्रासेप्सिक) परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और लोगों के लिए प्रकृति के योगदान के अन्य पहलुओं के बारे में बताता है।उन्होंने मछली और व्यवसायिक मत्स्य, कीट और फसल में परागण करने वाले, पौधों और वानिकी उत्पादों, कई अलग-अलग फसलों और उनके जंगली पूर्वजों सहित प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता में अच्छी तरह से संबंध पाया। पल्कोवाक्स ने कहा कई मामलों में जब हम विविधता खो देते हैं, तब कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यवसायिक मत्स्य पालन है, जहां मछली की विविध प्रजातियों के भंडार समग्र आबादी को स्थिर करने में मदद करते हैं।उदाहरण के लिए, सैल्मन की उप-प्रजातियां स्थानीय रूप से विभिन्न जलक्षेत्रों की स्थितियों के अनुकूल हैं, जिससे समग्र आबादी स्थिर बनी रहती है क्योंकि पर्यावरणीय उतार-चढ़ाव कुछ आबादी में गिरावट और दूसरों में वृद्धि का कारण बनते हैं। सैल्मन की आबादी बांधों के कारण कम हो जाती है, जो महत्वपूर्ण रूप से उनके अंडे वाले स्थान से उप-विभाजन को रोकते हैं, जो आनुवंशिक विविधता को कम कर सकते हैं। सैल्मन में अंतर-भिन्नता का नुकसान आबादी के चक्रों को जन्म दे सकता है जो मत्स्य पालन में लंबे समय के लिए हानिकारक हैं।

डेस रोचेस ने कहा कि लोग लंबे समय से घरेलू और कृषि संबंधी महत्वपूर्ण प्रजातियों की भिन्नता पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा हमारा इतिहास सैकड़ों पालतू प्रजातियों का रहा है, इन प्रजातियों के भीतर असामान्य और फायदा पंहुचाने वाली विशेषताएं होती है। हमने अक्सर इसे बहुत दूर कर दिया है और इस तरह घरेलू प्रजातियों में महत्वपूर्ण आनुवंशिक विविधता को खो दिया है। हम इस विविधता को बहाल करने के लिए अधिक आनुवंशिक रूप से बदलने वाले जंगली प्रकार या पैतृक आबादी के साथ विजाति प्रजनन (आउटब्रेडिंग) पर निर्भर करते हैं।

पल्कोवाक्स ने कहा कि औषधीय महत्व वाले पौधे की प्रजाति के भीतर (इंट्रासेप्सिक) भिन्नता महत्वपूर्ण है। एक ही पौधे की विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न औषधीय गुण हो सकते हैं, जैसे कि अलग-अलग एंटीमाइरियल दवाएं जो उन पौधों की आनुवांशिक विविधता पर निर्भर करती हैं जिनसे वे उत्पन्न होती हैं।उन्होंने कहा कि पश्चिमी विज्ञानिकों ने प्रजातियों के स्तर के विलुप्त होने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, केवल जीवों के सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किए गए समूहों के भीतर की विविधता का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्वारा मूल्यांकन की गई सभी प्रजातियों में से केवल 1 प्रतिशत प्रजातियों का ही निचले स्तर का मूल्यांकन किया गया है और उनमें से कई की विविधता में गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यावहारिक कदम हैं जो अब उठाए जा सकते हैं, इस विविधता का बेहतर ढंग से दस्तावेजीकरण करना, जैव विविधता को संरक्षित करना और लोगों की भलाई के लिए इसके योगदान की रक्षा करना है।

लॉकडाउन के बाद 12 से अधिक जानलेवा रासायनिक हादसे

एक दर्जन से अधिक रिपोर्ट किए गए औद्योगिक हादसों में प्लांट या फैक्ट्री की लापरवाही का मामला लगातार सामने आया है। इन हादसों के शिकार हुए सैकड़ों मजदूर अब भी लापता हैं।

देश में लॉकडाउन के बाद औद्योगिक रासायनिक ईकाइयों में जानलेवा हादसों का दस्तूर जारी है। देश के अलग-अलग औद्योगिक कोनों से 12 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हादसों में मजदूरों की जिंदगियां चली गई हैं और कई अब भी लापता हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फिलहाल गुजरात के भरूच में एग्रो-केमिकल प्रमुख यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड (यूपीएल) झागड़िया प्लांट में जानलेवा घटना पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। 23 फरवरी, 2021 को हुए इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई थी।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस एके गोयल ने फिलहाल ताजा यूपीएल प्लांट मामले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपीएल के निदेशक, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ और जिलाधिकारी को नोटिस भी दिया है। ट्रिब्यूनल ने 25 फरवरी, 2021 को अपने आदेश में कहा है कि बीते कुछ महीनों में एनजीटी में रासायनिक हादसों के कई मामले आए हैं। इनमें कई समितियों ने रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को सौंपी है। ऐसे में यूपीएल प्लांट का मामले देखने वाली समिति इन रिपोर्ट को भी आधार बना सकती है। एनजीटी ने बीते कुछ महीनों में एक दर्जन से ज्यादा औद्योगिक ईकाइयों में घटित जानलेवा मामलों पर अलग-अलग तारीखों पर आदेश दिए हैं।एनजीटी के आदेशों के आधार पर देखें तो ट्रिब्यूनल ने 1 जून, 2020 को विशाखापत्तनम के एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में आदेश दिया।

समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है इंसानी कोलाहल

इंसान शोर न केवल समुद्रों में ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, साथ ही उसकी वजह से प्राकृतिक ध्वनियां भी गुम होती जा रही हैं जो समुद्री जीवों को खतरे में डाल रही हैं

समुद्रों में बढ़ते इंसानी शोर से जीवों के जीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। इस शोर से उनकी भोजन, प्रजनन और शिकारियों से बचने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। कहते हैं हवा की तुलना में शोर पानी में बहुत तेजी से दूर तक जाता है। यह बात समुद्री जीवन के लिए खतरा बन गई है। समुद्र में रहने वाले कई जीवों का विकास इस तरह से हुआ है कि वो अपने जीवन के कई पहलुओं के लिए अपने और अपने आसपास की ध्वनि पर निर्भर करते हैं, पर जिस तरह से समुद्री वातावरण में इंसानी शोर और कोलाहल घुल गया है, उसमें इन जीवों की आवाज गुम होती जा रही है जो उन जीवों के जीवन को खतरे में डाल रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इंसानों के कारण समुद्र में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसके शोर से प्राकृतिक ध्वनियां गुम होती जा रही हैं। जिसका असर छोटी झींगा से लेकर हजारों किलो वजनी व्हेल पर भी पड़ रहा है।

इसे समझने के लिए इस शोध में 500 से भी ज्यादा शोधपत्रों का विश्लेषण किया गया है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ता प्रदूषण वैसे भी समुद्रों और वहां रहने वाले जीवों पर व्यापक असर डाल रहा है इंसानी शोर के लिए बढ़ते जहाज, समुद्रों में तेल और गैस के लिए बढ़ती गतिविधियां और भूकंपीय सर्वेक्षण के लिए किया विस्फोट शामिल है। इन सभी ने मिलकर पानी के नीचे की आवाज को बहुत हद तक बदल दिया है। इसका असर व्हेल्स, डॉलफिन जैसे जीवों पर पड़ रहा है। कई बार यह जीव इस शोर से बहरे तक हो जाते हैं। यह जीव अपना पथ ढूंढने के लिए ध्वनि पर भरोसा करते हैं ऐसे में इसके चलते यह अपने पथ से भी भटक जाते हैं।

यह उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते है कि कई मछलियां और समुद्री जीव एक दूसरे से बात करने के लिए ध्वनि की मदद लेते हैं। इसकी मदद से वो अपने लिए भोजन और प्रजनन के बेहतर स्थानों का पता लगाते हैं। इसके साथ ही ध्वनि की मदद से वो शिकारियों और आने वाले खतरे का पता लगाते हैं।

हरियाणा : रकबा/पैदावार बढ़ने के बाद भी घटी कृषि विकास दर

एजेंसियां: बेशक हरियाणा में खेती का रकबा बढ़ रहा है और फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है, बावजूद इसके पिछले कई सालों से कृषि विकास दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 12 मार्च को हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आमदनी के मुकाबले लागत में अधिक वृद्धि की वजह से ऐसा हो रहा है।

वित्त वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, हरियाणा में खेती की विकास दर 4.3 फीसदी होने की संभावना है। जो अब तक सबसे कम है। जबकि प्रदेश के विकास में कृषि का कुल योगदान महज 18.9 फीसदी अनुमानित की गई है। 2016-17 में कृषि विकास दर 7.9 फीसदी, 2017-18 में 6.1 फीसदी, 2018-19 में 5.3 फीसदी और 2019-20 में 4.5 फीसदी थी, जबकि इस दौरान प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 2019-20 में 16.6 प्रतिशत और 2018-19 में 17.5 फीसदी ही रहा। जबकि साल दर साल खेती का रकबा और पैदावार दोनों में इजाफा हुआ है। एक नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के वक्त गेहूं 7.43 लाख हेक्टेयर, धान 1.92 लाख हेक्टेयर समेत मिलाकर खाद्यान्न की पैदावार 35.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती थी। इसके अलावा गन्ना, ऑयल सीड्स, कपास मिलाकर 45.99 लाख हेक्टेयर पर बिजाई हुई थी। गेहूं की पैदावार 10.59 लाख टन, धान की पैदावार 2.23 लाख टन समेत अन्य खाद्यान्न की कुल पैदावार 25.92 लाख टन हुई थी। इस दौरान प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन 4106 किलोग्राम, धान 2557 किलोग्राम था। इस समय प्रदेश के विकास में कृषि का योगदान 67 प्रतिशत था।

2016-17 में गेहूं 25.42 लाख हेक्टेयर, धान 13.85 लाख हेक्टेयर समेत मिलाकर खाद्यान्न की पैदावार 45.37 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती थी। गेहूं की पैदावार 123.1 लाख टन, धान 44.51 लाख टन रहा, जबकि प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन 4842 किलोग्राम और धान 3214 किलोग्राम पहुंच गया। इसके अलावा गन्ना, ऑयल सीड्स, कपास मिलाकर 65.02 लाख हेक्टेयर पर बिजाई होती थी।

2017-18 में गेहूं 25.31 लाख हेक्टेयर, धान 14.22 लाख हेक्टेयर समेत मिलाकर खाद्यान्न की पैदावार 45.32 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती थी। गेहूं की पैदावार 122.65 लाख टन, धान 48.8 लाख टन रहा, जबकि प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन 4847 किलोग्राम और धान 3432 किलोग्राम पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गेहूं 25.53 लाख हेक्टेयर, धान 14.47 लाख हेक्टेयर समेत मिलाकर खाद्यान्न की पैदावार 45.58 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती थी। गेहूं की पैदावार 125.73 लाख टन, धान 45.16 लाख टन रहा, जबकि प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन 4925 किलोग्राम और धान 3121 किलोग्राम पहुंच गया।

2019-20 में गेहूं 25.34 लाख हेक्टेयर, धान 15.59 लाख हेक्टेयर समेत मिलाकर खाद्यान्न की पैदावार 47.03 लाख हेक्टेयर भूमि पर पहुंच गई। गेहूं की पैदावार 118.77 लाख टन, धान 51.98 लाख टन रहा, जबकि प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन 4687 किलोग्राम और धान 3334 किलोग्राम पहुंच गया।

कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा कहते है कृषि विकास दर और विकास में कृषि का योगदान घटने का साफ अर्थ है कि कृषि की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है।

सीजन में चने का साग न खाया तो क्या खाया?

विभा

अगर चने का नर्म साग सर्वसुलभ हो जाए तो इस पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी

उत्तर प्रदेश में चने के साग में अक्सर दाल मिलाकर बनाया जाता है । सर्दियों के दौरान दिल्ली में हरी पत्तेदार सब्जियों से भरी गाड़ियों के नजारे आम हैं। फेरी वाले सरसों, पालक और मेथी जैसे तरह-तरह के साग बेचते दिखते हैं। हमेशा तो नहीं लेकिन कभी-कभार उनके पास चने का साग भी मिल जाता है। चना (साइसर एरीटिनम) दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फली है, जिसकी खेती इसके प्रोटीन से भरपूर बीजों के लिए की जाती है न कि हरी पत्तियों के लिए। यही वजह है कि इसका साग हमें बाजार में बहुत मुश्किल से मिलता है।

चने की पैदावार को बढ़ाने के लिए इसकी कोमल पत्तियों को बढ़ रहे पौधों से तोड़ लिया जाता है। इससे पौधा घनी झाड़ीनुमा और पौधा अधिक बीज पैदा करने में सक्षम हो जाता है। ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड की उपस्थिति की वजह से इसकी पत्तियों में थोड़ी खटास होती है। हालांकि, पत्तियों को धो देने से उनकी खटास चली जाती है। गांवों में बच्चों को स्नैक्स की तरह इन पत्तियों का लुत्फ उठाते देखना आम है। बच्चे केवल शीर्ष पर मौजूद नई पत्तियों को ही तोड़ते हैं, इसलिए कि सान भी इससे नाराज नहीं होते। यह साग बाजार में बमुश्किल ही मिल पाता है। लेकिन, अगर दुकानदार के पास आपको यह पत्तियां न मिलें, तो उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें घर पर ही उगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस माइक्रोग्रीन्स को उगाने के तौर-तरीकों को सीखने की जरूरत है। बस पहली दो पत्तियों के आने के तुरंत बाद ही पौधों की छंटाई कर देने की जगह उसे कुछ समय तक बढ़ने देना चाहिए, जब तक टहनियों में और भी पत्तियां न निकल आएं। करीब 10 दिनों में पर्याप्त संख्या में पत्तियां निकल आती हैं।

माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए छोटे, भूरे बीजों वाली देसी किस्म बढ़िया होती है। बीज को एक दिन के लिए पानी में भिगोएं, फिर उन्हें रोप दें और मिट्टी की एक पतली परत से ढंक दें। उन्हें सूरज की रोशनी में बढ़ने दें और पौधों को नियमित तौर पर पानी देते रहें। ये काफी तेजी से बढ़ते हैं, इसी वजह से स्कूलों में बच्चों को चने के बीजों से ही अंकुरण के बारे में पढ़ाया जाता है।

पौष्टिक तत्वों से भरपूर

अध्ययनों से पता चला है कि चने की पत्तियां बहुत पौष्टिक होती हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएन्ट मिनरल्स आयरन, जिंक, मैंग्नीज, कॉपर और बोरोन) दोनों का बहुत अच्छा स्रोत हैं। यही नहीं, साल 2003 में द जर्नल ऑफ द साइंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि इनमें से अधिकतर मिनरल्स का स्तर इस साग में पत्तागोभी और पालक से कहीं अधिक है।

पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना के शोधार्थियों के मुताबिक, 100 ग्राम सूखी पत्तियों में 93 मिलीग्राम आयरन होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन पत्तियों के पाउडर का इस्तेमाल चपाती और पूरी जैसे पारंपरिक खाने में किया जाना चाहिए। परंपरागत रूप से साग केवल उन राज्यों में ही भोजन का हिस्सा है, जहां चने की खेती की जाती है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और बिहार शामिल हैं। हालांकि, पत्तियों को सुखाकर उनका भंडारण किया जा सकता है, लेकिन सहजन की पत्तियों के विपरीत अभी तक इसके लिए कोई औपचारिक बाजार मौजूद नहीं है। चना उत्पादन में अग्रणी भारत जैसे देश के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया का 65 फीसदी चना यहीं पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में दाल में साग डालकर पकाया जाता है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें बहुत कम मसालों का उपयोग किया जाता है, ताकि साग की खटास का लुत्फ उठाया जा सके।

बीते कुछ वर्षों के दौरान पाया गया है कि यह फलीदार प्रजाति खतरे में है। पश्चिमी ईरान से दक्षिण पूर्व तुर्की तक फैले अर्द्धचंद्राकार उपजाऊ क्षेत्र में चने की फसल के तौर पर खेती (गृहीकरण) शुरू की गई थी। अध्ययनों से पता चलता है कि 10 हजार से अधिक वर्षों में चने के गृहीकरण की इस प्रक्रिया के दौरान इसकी 80 फीसदी आनुवांशिक विविधता खो गई।

सर्पदंश के खतरे से लाखों जिंदगियां बचा सकता है यह मॉडल

दयानिधि

यह मॉडल अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग मौसमों में सांप के काटने के पैटर्न का अनुमान लगाने में बहुत सटीक साबित हुआ है।

दुनिया भर में हर साल लगभग 18 लाख लोग सांप के काटने के शिकार होते हैं, जिसमें से लगभग 94 हजार लोग मारे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में, सांपों के काटने को मृत्यु का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इनमें विशेषकर किसान होते हैं जो अपने खेतों में अक्सर सांपों का सामना करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक सांपों के काटने को 50 फीसदी कम करने के लिए एक रणनीतिक योजना शुरू की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण आधार तथा इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देना है। तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित एक अंतरराष्ट्रीय शोध समूह ने हाल ही में सांपों के काटने के अनुमान लगाने के लिए एक अनूठा सिमुलेशन मॉडल बनाया है, जो समय और स्थान दोनों में किसानों और सांपों के परस्पर प्रभाव की बेहतर समझ पर आधारित है। मॉडल का उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर सांप के काटे जाने की आशंका को निर्धारित करना है, जिनमें चावल के खेतों से लेकर चाय के बागान तक शामिल हैं, इसनें अलग-अलग समय पर होने वाली घटनाओं जिनमें वर्ष के महीनों और दिनों के घंटे तक हैं।

अध्ययन श्रीलंका में व्यापक शोध और आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जहां हर साल लगभग 30 हजार लोग सांप के काटने के शिकार होते हैं, जिसमें से लगभग 400 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अध्ययन में 6 प्रकार के सांपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो दुनिया के सबसे विषैले सांपों में शामिल हैं जिनमें कोबरा, रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, हंप-नोज सांप, कॉमन क्रेट और सीलोन क्रेट शामिल हैं। इन सबसे उन किसानों का सामना होता है जो तीन सबसे आम फसलें उगाते हैं जिनमें चावल, चाय और रबड़ की फसल शामिल है। मॉडल इस बात का अनुमान लगाता है कि रसेल वाइपर फरवरी और अगस्त के दौरान चावल के खेतों में होते हैं जहां ये लोगों को अक्सर काटते हैं, जबकि हंप-नोज सांप अप्रैल और मई में जब रबर का वृक्षारोपण होता है ये उस जगह पर पाए जाते हैं। मॉडल यह भी निर्धारित करता है कि अध्ययन किए गए क्षेत्र के दक्षिणपूर्वी हिस्से में, सांप के काटने की सबसे अधिक घटनाओं के लिए रसेल वाइपर को जिम्मेदार माना जाता है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है, जबकि इस क्षेत्र के अन्य हिस्सों में कम घातक हंप-नोज सांपों के काटने की घटनाएं सबसे आम हैं। ईयाल गोल्डस्टीन बताते हैं हमने यह पहला अनूठा मॉडल बनाया है, जिसमें दोनों पक्षों सांपों और मनुष्यों के व्यवहार पैटर्न को शामिल किया गया है। विभिन्न समय और स्थानों पर खतरों की पहचान करना और उनके बारे में चेतावनी देना इस मॉडल का उद्देश्य है। उदाहरण के लिए, मॉडल कम खतरे और अधिक खतरे वाले क्षेत्रों के बीच अंतर कर सकते हैं, अंतर जो प्रति 1 लाख लोगों पर सांपों के काटने की संख्या से दोगुना हो सकता है। यह शोध प्लोस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

डॉ. मर्रे बताते हैं कि सांप और लोग दोनों अपने काम के लिए दिन के अलग-अलग समय पर, अलग-अलग मौसमों और विभिन्न प्रकार की जगहों में जाते हैं। मॉडल उन सभी को कैप्चर करता है जो उन क्षेत्रों में लोगों और सांपों के बीच सामना होने की आशंका होती है। डॉ. इवामुरा जोर देकर कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण गणितीय रूप से सांपों और मनुष्यों के परस्पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह तंत्र को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण है जो सांपों के काटने का कारण बनता है।

सामाजिक और आर्थिक खतरे वाले कारकों पर, हमने पारिस्थितिक पहलुओं को चुना है - जैसे कि सांपों की गतिविधि और निवास स्थान, जलवायु और वर्षा का प्रभाव और किसानों और सांपों के संबंधित व्यवहार, जिसमें एक दूसरे से सामना होने का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। श्रीलंका में मौजूदा आंकड़ों के विरुद्ध, मॉडल अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग मौसमों में सांप के काटने के पैटर्न का अनुमान लगाने में बहुत सटीक साबित हुआ है। अब शोधकर्ता उन जगहों पर मॉडल को लागू करने की सोच रहे हैं जहां अभी तक सांपों के काटने के बारे में सटीक आंकड़े नहीं हैं। साथ ही इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाने के लिए करेंगे - जैसे बढ़ती वर्षा, सांपों की अधिक गतिविधि के लिए, साथ ही साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन और सांपों के आवास आदि।

डॉ. इवामुरा ने निष्कर्ष में कहा कि हमारा मॉडल सांपों के काटने की घटनाओं को कम करने की नीतियों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और चेतावनी के लिए एक उपकरण के रूप में काम करने, जागरूकता बढ़ाने और मानव जीवन को बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, हम इस अध्ययन को एक व्यापक परियोजना में पहले चरण के रूप में मानते हैं।

भविष्य में हम वास्तविक दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रकृति संरक्षण नीतियों दोनों का समर्थन करने के लिए मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष के लिए अधिक जटिल मॉडल विकसित करेंगे।

E ZONE CARE

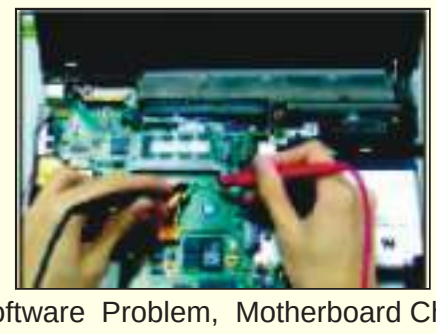

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।